को हम एक्सपोर्ट करें और हैंडलूम के लिए या पावर लूम के लिए और मिल्स के लिए अगर काटन नहीं रहे, प्राइसेस बढ़ जाएं तो हमारे लिए कंट्री के लिए बड़े तकलीफ देंगे तो मैं आनरेबल मैंबर को यह बताना चाहता हूं कि अब तक कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काटन पैदा करके एक्सपोर्ट करने की खास तौर से इजाजत देने की कोई ऐसी स्कीम नहीं है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : किसान अगर खुद उसको प्रोसैस करना चाहे तो लाइसेंस कोटा परमिट की, रिश्वत देने के बिना यह लेने की एक किसान को इजाजत होगी कि लाइसेंस के बिना वह सब कुछ कर सके ।

श्री जी० वेंकट स्वामी : यह एक नया इन्फार्मेशन है, सभापति जी, रिश्वत के साथ लाइसेंस मिलने की बात मेरे को पहली मर्तबा है, क्योंकि मुझे 2 महीने हुए हैं मिनिस्टर बने हुए, लाइसेंस रिश्वत के साथ मिलता है यह मुझे नहीं मालूम । अगर ऐसी कुछ बात है तो मैं जरूर उसके ऊपर गौर करूंगा ।

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Mentay Padmanbham.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir, two issues are involved in this. One is to give remunerative prices to the cotton growers and the other issue is to supply hank yarn to the handloom sector at a reasonable price. So, these two are rather irreconcilable issues.

SHRI NARAYANASAMY : It is a continuing issue.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : To get over this problem, the Government had, over a period, subsidised the yarn supplies to the weavers. This subsidised supply to the weavers is not working well and is full of loop-holes. I would like to know from the honourable Minister whether he is goining to revise this subsidised supply of yarn to the handloom sector, particularly to ward off lack of work for the handloom weavers and to provide more work to the weavers. I would like to know whether he will revise this subsidised system of supplying hank yarn to the handloom weavers. This is an important question.

श्री जी० वेंकट स्वामी : सभापति जी, पहले यह हैंक यार्न सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेज वगैरह के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से 5 परसेंट सबसिडी दी जाती थी और हैंक यार्न पूरी तरह से वीवर्स को सप्लाई होता था, मगर 2 परसेंट होने की वजह से, मैं फिगर अभी तक बता चुका हूं दो वर्ष पूर्व जिस तरह से हैंक यार्न पूरी तरह से सप्लाई हुआ इस साल नहीं हो सका क्योंकि 5 परसेंट से 2 परसेंट सबसिडी किया गया है । ट्रांसपोर्ट चार्जेज और बहुत सारी चीजें हैं एक्सपेंडीचर हैं, तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, फाईनांस मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मेरी रेक्विजीशन गई है इनस्टैड आफ 2 परसेंट 5 परसेंट अगर किया जाए तो हैंक यार्न पूरी तरह से इस साल वीवर्ज को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे ।

Price of Consumer Items

*382. SHRIMATI VEENA VERMA :†
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the recent increase in support prices of wheat, rice and other products contributed to the rise in prices of other consumer items also like soaps,

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Veena Verma.

Table 1

Movement in Price Indices of Common Items.

(Per cent)

Items	WPI			CPI				
	Indices			Indices			% Change	
	Nov. 1992	Jan. 1993	% Change	Nov. 1992	Dec. 1992	Jan. 1993	Dec./ Nov.	Jan./ Nov.
GENERAL	231.7	230.3	—0.6	244.0	243.0	241.0	—0.4	—1.2
1. Rice	251.7	248.2	—1.4	241.1	239.5		—0.7	
2. Whole Wheat	223.4	233.2	4.4	219.8	218.9		—0.4	
3. Wheat atta	254.0	267.7	5.4	207.5	208.6		0.5	
4. Jowar	236.6	218.6	—7.6	307.2	305.6		—0.5	
5. Bajra	193.6	182.2	—5.9	191.0	199.1		4.2	
6. Moong	235.2	250.9	6.7	288.3	284.5		—1.3	
7. Gram	210.9	239.2	13.4	266.3	278.4		4.5	
8. Masur	220.3	215.5	—2.2	265.6	262.4		—1.2	
9. Arhar	287.6	288.0	0.1	295.1	291.1		—1.3	
10. Urad	282.4	269.5	—4.6	258.8	253.7		—2.0	
11. Coconut oil	344.4	348.7	1.2	328.3	327.7		—0.2	
12. Groundnut oil	229.9	206.6	—10.1	248.0	237.3		—4.3	
13. Mustard oil	219.3	207.6	—5.3	225.7	220.3		—2.4	
14. Vanaspati	267.3	257.4	—3.7	251.0	244.0		—2.8	
15. Goat Meat	277.0	283.1	2.2	271.4	274.3		1.0	
16. Fresh fish	297.3	313.9	5.6	265.0	274.4		3.5	
17. Milk	274.4	274.6	0.1	240.6	238.1		—1.1	

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Salt	214.4	213.6	—0.4	296.8	297.5	0.2
19.	Chillies	324.4	297.9	—8.2	373.1	351.2	—5.9
20.	Onions	167.1	209.3	25.3	214.3	245.0	14.3
21.	Potatoes	308.1	191.7	—37.8	243.9	219.2	—10.1
22.	Sugar	176.3	175.7	—0.3	189.3	188.1	—0.6
23.	Gur	190.6	192.6	1.0	282.9	277.8	—1.8
24.	Tea leaves	283.7	297.3	4.8	271.0	270.8	—0.1
25.	Soft Coke	320.0	320.0	0.0	295.8	297.1	0.4
26.	Kerosene oil	146.7	146.7	0.0	147.0	147.0	0.0
27.	Matchboxes	144.6	144.3	—0.2	169.1	173.1	2.3
28.	Washing Soap	196.0	196.0	0.0	206.9	207.2	0.1
29.	Long cloth	170.8	169.2	—0.9	231.7	225.9	—2.5
30.	Dhoties	193.3	198.5	2.7	187.2	181.9	—2.8
31.	Sarees				184.4	184.1	—0.2
	Composite Index (Essential Commodities)	231.9	230.7	—0.5	236.7	234.7	—0.8

Base : WPI=1981-82=100 CPI=1982=100

spices, vegetables, fruits and edible oils; and

(b) if so, what are the comparative, itemwise, prices as in November, 1992 and January, 1993 and the overall percentage increase in respect of consumer items during the period, indicating also the Consumer Price Index number in each of the months.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The increase in support prices of wheat, rice and other products has not contributed to rise in the wholesale and retail prices of these and other consumer items like soaps, spices, vegetables, fruits and edible-oils because there is a general decline in the market price of various primary products. The latest inflation rate as on 6th March, 1993 at 6.8% signals continued downtrend in the current inflation rate.

(b) The comparative wholesale and consumer prices indices of different essential commodities along with the annual rate of inflation as in November, 1992 and January, 1993 are given in *Tables* 1 & 2.

Table–2

Annual Rate of Inflation in Essential Commodities

(Per cent)

Items	WPI		CPI		
	Nov. 1992	Jan. 1993	Nov. 1992	Dec. 1992	Jan. 1993
GENERAL	9.1	6.9	8.4	8.0	5.7
1. Rice	12.5	3.7	15.3	11.2	
2. Whole wheat	9.4	—7.2	16.8	9.4	
3. Wheat atta	14.4	13.4	8.7	4.1	
4. Jowar	11.9	—10.0	6.2	5.8	
5. Bajra	—7.7	—24.9	—20.8	—23.8	
6. Moong	—1.5	5.6	13.1	10.7	
7. Gram	8.5	21.7	5.8	11.7	
8. Masur	—15.3	—9.7	—8.5	—9.9	
9. Arhar	—10.6	—9.9	—8.7	—9.0	
10. Urad	—11.5	—13.7	—2.1	—2.3	
11. Coconut	1.8	6.8	—8.1	—6.7	
12. Groundnut oil	—16.1	—23.2	—14.3	—16.4	
13. Mustard oil	—15.5	—20.4	—12.5	—16.4	
14. Vanaspati	—11.1	—12.1	—12.5	—15.0	
15. Goat Meat	13.9	16.1	11.2	11.1	

16. Fresh fish	34.5	32.9	11.8	11.8
17. Milk	13.2	13.4	15.0	12.8
18. Salt	4.0	2.0	4.7	5.0
19. Chillies	—22.1	—21.1	—7.5	—13.8
20. Onions	—34.0	64.0	—29.5	8.1
21. Potatoes	—31.4	—10.0	—29.9	—22.7
22. Sugar	12.4	9.1	12.4	10.7
23 Gur	13.7	29.3	18.1	20.5
24. Tea leaves	6.7	15.0	2.2	1.8
25. Soft Coke	26.1	0.0	12.4	12.7
26. Kerosene oil	0.8	0.0	1.7	1.7
27. Matchboxes	4.5	4.3	12.0	13.2
28. Washing Soap	4.4	4.4	5.8	5.0
29. Long cloth	10.2	9.2	14.2	11.5
30. Dhoties	9.7	12.7	8.7	4.6
31. Sarees			9.3	9.3
Composite Index (Essential Commodities)	5.7	4.0	5.3	3.9

Base : WPI=1981-82=100 CPI=1982=100.

श्रीमती वीणा वर्मा : **सभापति महोदय**, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि सपोर्ट प्राइस बढ़ना एक निरंतर प्रक्रिया है और सपोर्ट प्राइस बढ़ने से देखा गया है कि कंजूमर प्राइस भी बढ़ती है, अब कंजूमर प्राइस न बढ़े या कम बढ़े अर्थात सपोर्ट प्राइस बढ़ने से ज्यादा प्राइस न बढ़े और कम रहे कंट्रोल में रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? सरकार खास तौर से क्या कर रही है कि सपोर्ट प्राइस जब बढ़े तो कंजूमर प्राइस न बढ़े और मेरे प्रश्न का "बी" पार्ट है कि मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया है कि गेहूं, चावल व अन्य उत्पादों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनके मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि विभिन्न मूल उत्पादों के बाजार मूल्यों में गिरावट आई है । तो यह मुद्रास्फीति की दर में जो 6.8 प्रतिशत की दर से लगातार गिरावट की प्रगति दिखायी दी है, इस गिरावट की प्रगति का क्या कारण है और इस इनफ्लेशन को रोकने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

डा० अबरार अहमद : सर, माननीय सदस्या ने पहली बात तो यह पूछी है कि जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं और उसके कारण से कंजूमर पर भी उसका सीधा असर पड़ता है और मूल्य-वृद्धि होती है, तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बात ठीक उसी प्रकार की है जैसे कि एक बाप के दो बेटे होते हैं वैसे ही सरकार के लिए कंजूमर भी एक बेटा है और किसान भी एक बेटा है। जब वह किसान को कीमत बढ़ाती है उसकी हालत देखकर तो निश्चित रूप से कंजूमरज का भी ध्यान रखती है कि इतनी कीमत न बढ़ायी जाए जिससे कि कंजूमर पर अत्यधिक भार पड़ जाएं और ऐसा भी न हो कि सपोर्ट प्राइस बिल्कुल न बढ़ायी जाए या बहुत कम बढ़ायी जाए जिससे कि किसान भूखा मर जाए । तो सपोर्ट प्राइस बढ़ाते समय ये दोनों बातें ध्यान में रखी जाती हैं कि किसान भी जीवितरहे, वह उस पैदावार से अपनी आजीविका का उपार्जन कर सके और कंजूमर पर भी बहुत अधिक भार न पड़े । इन

दोनों बातों में सामंजस्य बिठाकर तालमेल बिठाकर सपोर्ट प्राइस बढ़ायी जाती है । दूसरी बात, माननीय सदस्य ने यह जानना चाही है कि इनफ्लेशन की जो रेट घटी है, उसके लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं और उसके क्या कारण हैं ? सभापति महोदय, इनफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए और उसको घटाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उसके अंदर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ फिस्कल डेफेसिट, टाइट मॉनीटरी पॉलिसी, वीट और राइस के घरेलू स्टाक में वृद्धि, टाइमली इम्पोर्ट के द्वारा इम्पोर्ट कम्पनसेशन मेजर्स को रिलेक्स करके, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि द्वारा, खर्चे पर नियंत्रण द्वारा वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ाकर और फायनेंसियल सेक्टर रिफार्म एस० एल० आर० एवं सी० आर० आर० में कमी कर के ।

श्रीमती वीणा वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि सरकार के दो बेटे हैं, एक तो किसान और दूसरा उपभोक्ता । तो कीमतों में कुछ वृद्धि तो इन दो बेटों की वजह से होती है . . . **(व्यवधान)** . . .

श्रीमती कमला सिन्हा : सरकार उपभोक्ता और किसान का बेटा है न कि सरकार के ये दो बेटे हैं ।

श्रीमती वीणा वर्मा : मैं तीसरा बेटा और बताने जा रही हूं ।

MR. CHAIRMAN : Why no daughters ?

SHRIMATI KAMLA SINHA : Sir, it is male chauvinism !

श्रीमती वीणा वर्मा : कुछ मूल्य-वृद्धि तो कंजूमर सपोर्ट प्राइस की वजह से होती है और कुछ मूल्य-वृद्धि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कि तीसरा बेटा कहें, उसकी वजह से होती है और देखा गया है कि मनमाने ढंग से विक्रेता प्राइस लगाते हैं या आयटम्स पर प्राइस की लिस्ट नहीं लगी होती है । एक समय था जब श्री मोरारजी देसाई हमारे प्रधान मंत्री थे, उस समय एक ऑर्डर निकाला गया था कि ये प्राइस लिस्ट या प्राइस सूची लगायी जाएगी और वस्तु का एक्जैक्ट मूल्य लगाया जाएगा, रिटेल प्राइस न लगाकर टोटल मूल्य लगाया जाएगा । तो यह बंद हो गया । अब क्या सरकार इसको फिर से चलाएगी या फिर से ऐसे आर्डर देने का एसोरेन्स देगी ? दूसरी चीज, सरकार के डिस्ट्रिब्यूशन केन्द्र एक तो केन्द्रीय भंडार है, दूसरा सुपर बाजार है, जहां से सरकार चीजों को बिकवाती है, फिर फेयर प्राइस शाप्स हैं और चौथे प्राइवेट विक्रेता हैं । आज ही अखबार में प्राइस इंडेक्स में बताया गया है कि बहुत सी चीजों के, जैसे दाल, चने आदि के भाव केन्द्रीय भंडार और सुपर बाजार में फर्क है । केन्द्रीय भंडार में जैसे अरहर की दाल 13 रुपए 60 पैसे है तो वही दाल सुपर बाजार में 13 रुपए 95 पैसे है । इसी तरह जो प्राइस लिस्ट इसमें है, उसमें हरेक में 50 पैसे या 75 पैसे या 15 पैसे या बीस पैसे का फर्क केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार में है । एगमार्क बेसन, जो एक ही क्वालिटी का है, उसका भाव केन्द्रीय भण्डार में 13 रुपए 25 पैसे है और सुपर बाजार में 13 रुपए 10 पैसे है या 12 रुपए 95 पैसे है, एगमार्क आटे के दाम में भी करीब 90 पैसे का फर्क है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यह फर्क क्यों होता है ? सरकार की चीजें केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार में एक दाम पर क्यों नहीं बिकती ? इसको बराबर करने के लिए सरकार क्या करेगी ? क्या कोई ऐसे कदम उठाएगी, जिससे कि दाम एक से रहें ?

सभापति महोदय, महिलाओं को अन्नदाता कहा जाता है, अन्नपूर्णा भी

कहा जाता है । तो कंज्यूमर मूवमेंट को और तेज तथा प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या महिला मंडलों को फेयर प्राइस शॉप्स देने पर भी सरकार विचार करेगी ?

डा० अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और उसमें खासतौर से जो केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार, प्राइवेट विकेता और उचित मूल्य की दुकानों में एक ही वस्तु के जो अलग-अलग भाव होते हैं, उनके कारणों के बारे में जानना चाहा है । तो मैं उन्हें यह बताना चाहुंगा कि यहां तक सवाल उचित मूल्य की दुकानों का है, तो वहां तो जो भी वस्तु दी जाती है वह सबसिडाइज होती है, जो एक गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए दी जाती है । इसके बाद यहां तक खुले बाजार की बात है, वहां व्यवसायी अपने सारे खर्चों को देखते हुए, इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, बाजार के खुले भाव को देखते हुए वस्तु का मूल्य निर्धारित करता है । माननीय सदस्य ने सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार के बारे में जो पूछा है तो मैं कहूंगा कि यह कोपरेटिव सेक्टर से दोनों ही सम्बन्धित हैं और इन दोनों में बहुत मामूली अंतर है । यहां तक केन्द्रीय भण्डार की बात है, यहां ओवरहेड बहुत कम होता है, केन्द्रीय भण्डार के अन्दर खासतौर पर एडवर्टाइजमेंट पर या पेकिंग पर या इस तरह की एक्टिविटिज पर बहुत कम खर्च किया जाता है, जबकि सुपर बाजार के अन्दर जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनके यहां एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं, पेकिंग पर खर्च करते हैं । दोनों में थोड़ा ओवरहेड पर फर्क होता है । उसकी वजह से, ओवरहेड अधिक होने की वजह से भाव में सुपर बाजार में थोड़ा ज्यादा भाव होता है और केन्द्रीय भण्डार में थोड़ा सा भाव कम होता है । इसके अलावा जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में माननीय सदस्या ने जानना चाहा था । मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि 31 मार्च, 1992 तक देश के अन्दर चार लाख फेयर प्राइस शॉप्स थीं, जिसमें रूरल एरिये के अंदर 3 लाख 5 हजार और अरबन सेक्टर में 94 हजार शॉप्स थीं । इस तरह करीब हर दो हजार की जनसंख्या पर एक दुकान थी । जो आपने पूछा कि इस पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के जरिए से हम इसको किस तरह से स्ट्रेन्थन करने जा रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जनवरी, 1992 से जो हमने एक स्कीम लॉंच की है, जिसमें 1700 ब्लाक में, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में है, रेगिस्तान के क्षेत्र में हैं, वीकर सेक्सन के क्षेत्र में हैं और ट्राइबल डवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर हैं, वहां यह दुकानें खोल रहे हैं और उसमें जो चीजें उन दुकानों में मिलती हैं वह तो देने का प्रावधान है ही, उसके साथ साथ चाय, दालें, साबुन देने की व्यवस्था करने का भी प्रयास कर रहे हैं । इसके अलावा अन्तिम बात, माननीय सदस्या ने पूछी कि महिलाओं को क्या इस सम्बन्ध में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वह दी जाएंगी । इस संदर्भ में मैं अभी तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन माननीय सदस्या का सुझाव अच्छा है और इसको मैंने नोट कर लिया है ।

श्रीमती वीणा वर्मा : और मूल्य-सूची के बारे में ?

डा० अबरार अहमद : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने एक बात और प्राइस लिस्ट के बारे में कही । आपने

एक उदाहरण दिया कि दुकानों में जिस प्रकार से पहले मूल्य-सूची लगी रहती थी, आपने तो जो बात कही है मूल्य-सूची लगाने के सम्बन्ध में, उस बारे में हम देखेंगे क्योंकि यह एक अच्छी व्यवस्था है और उससे कंज्यूमर को लाभ पहुंच सकता है । उसको वहां जाते ही पता लग सकता है कि अमुक वस्तु का मूल्य क्या है और उससे मनमाना मूल्य नहीं लिया जा सकता । तो हम देखेंगे कि वहां मूल्य-सूची लगाई जाए ।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव सिन्धे : सभापति जी, मैं प्रधान मंत्री जी को, सरकार को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्राइस कंट्रोल की है और इस बारे में जनता को जो आश्वासन दिया था, वह आश्वासन सरकार ने पूर्ण किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । महोदय, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि श्रीमती वीणा वर्मा जी ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि राशन शाप में जो बोर्ड लगा हुआ होता था, वह आज नहीं लगता है और एक ही दुकान में राशन शाप होती है और रिटेल शाप होती है तथा जो अनाज दिया जाता है राशन शाप में, वही रिटेल शाप में बेचा जाता है । सरकार इतना प्रयास करके कीमतें नीचे ला रही है, लेकिन उसका असर वहां नहीं पड़ता है । इसलिए एक्शन लेना जरूरी है ।

इसके साथ ही साथ दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि बहुत दिनों से और बहुत सालों से यह मांग हो रही है कि इन शॉप्स में दो सिस्टम होने चाहिए--एक तो इन्कम टैक्स पेयर के लिए और दूसरा नॉन इन्कम टैक्स पेयर के लिए । इतनी कीमतें नीचे आ रही हैं लेकिन गरीबों को इससे कोई मुनाफा नहीं होता है । तो इसके लिए कोई नई स्कीम सरकार के पास है क्या, कृपया यह बताएं ?

डा० अबरार अहमद : सभापति मोहदय, माननीय सदस्य ने जिस तरह से इन्कम टैक्स पेयर और नॉन इन्कम टैक्स पेयर के बारे में पूछा, उस संदर्भ में तो अभी कोई नई स्कीम नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है । इसके साथ ही साथ जो आपने एक और बात कही कि जब राशन की दुकान है, वहीं रिटेल की दुकान भी रहती है, ऐसे केसिस हमारे नोटिस में नहीं आए हैं । यदि माननीय सदस्य की जानकारी में हो कि कोई राशन शाप के साथ ही कोई रिटेल शाप भी वहां चल रही है तो . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI JAGESH DESAI : Everywhere, it is like that.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव सिन्धे : पूरे देश में है ।

डा० अबरार अहमद : सर, देश के अंदर तो क्या है, यह तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन अगर माननीय सदस्य का कोई स्पेसिफिक केस है, जिसके बारे में आपने मेंशन किया है, तो वह बताएं । जहां तक सुधारात्मक उपाय की बात है, सरकार निरन्तर प्रयास करती है कि जो भी सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, उसमें सुधार हो और उस सम्बन्ध में हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी माननीय सदस्य की कोई स्पेसिफिक शिकायत हों तो वे बताएं, हम निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास करेंगे ।

SHRI SOM PAL : Mr. Chairman, Sir, it is for the first time, in recent history, that the general prices of all agricultural commodities have shown a very steep fall compared to last year. Presently, whatever is the rate of inflation ruling, 91 per cent of it is attributable to the increase in the prices of non-agricultural commodities and only 9 per cent of it is attributable to agricultural commodities. If we take the non-food items, they have contributed, negatively, to the tune of 14 per cent. In

27 important market centres of India, agricultural commodities, including coarse grains, oilseeds and cotton, have been selling below the minimum support prices. Therefore, the reply given by the colleague of the hon. Finance Minister earlier in reply to the first question is wrong. What is the Government doing in this regard? Will they confirm the percentages given by me, namely; 91 per cent of inflation is due to increase in the prices of non-agricultural commodities and only 9 per cent is attributable to agricultural commodities?

MR. CHAIRMAN : Honourable Minister.

SHRI SOM PAL : Mr. Chairman, Sir, I would request the hon. Minister not to give platitudes; he should come out with specific replies.

डा० अबरार अहमद : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अपने सवाल का जो पहला पार्ट पूछा है कि कृषि उत्पादन वास्तव में नहीं बढ़े हैं, वैसे तो यह सवाल कृषि मंत्रालय का है । जो बात उन्होंने कही कि कृषि का कितना ..... **(व्यवधान)**

HRI SOM PAL : No, no, this belongs to the Finance Ministry. I am on inflation and contribution of agricultural commodities to inflation. But please don't say that .....

DR. ABRAR AHMED : Regarding inflation, I can give you the reply.

SHRI SOM PAL : I am on inflation only.

डा० अबरार अहमद : सर, जहां तक इंफ्लेशन का सवाल है, उसके अंदर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इंफ्लेशन का रेट जो नवम्बर, 1992 के अंदर 9.1 था वह घटकर जनवरी, 1993 के अन्दर 6.9 हुआ है और इंफ्लेशन घटने के जो कारण हैं वह मैंने विस्तृत रूप में अभी माननीय सदस्या ने जो पहला सवाल पूछा था, उसके संदर्भ में बताए हैं कि क्या कारण हैं और क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या मेजर्स हैं, जिनकी वजह से इंफ्लेशन रेट घटी है । जहां तक आपका कहना यह है कि उसके अंदर कृषि के उत्पादन की वजह से इंफ्लेशन रेट कम हुए हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं । एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अन्दर भी उत्पादन ... **(व्यवधान)**

SHRI SOM PAL : Mr. Chairman, Sir, I need your protection. He is giving a wrong information. This is a question which directly pertains to the Ministry of Finance, and I would request the senior Minister, Dr. Manmohan Singh, to come to my rescue .... (*Interruptions*) ... ...rather, to the rescue of hon. Dr. Abrar Ahmed. My pointed question is that contribution to the current rate of inflation is only to the tune of nine per cent through agricultural commodities and 91 per cent on account of non-agricultural commodities, and whether he would confirm this bifurcation or not. This is a question which pertains to the Ministry of Finance and is a matter of inflation. That's all.

MR. CHAIRMAN : Mr. Minister, any answer ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, it is certainly true that in the year 1992-93 the prices of agricultural commodities have not risen as fast as was the case in the previous year. To that extent it is certainly true that agricultural prices have been a moderating influence on inflation in the country.

SHRI SOM PAL : No, Sir, they have not been of moderate influence.

SHRI MANMOHAN SINGH : Yes, yes.

SHRI SOM PAL : No, no, they have shown a steep downward trend, a very steep decline.

MR. CHAIRMAN : This is only a different language. "Moderating" means the same thing.

SHRI SOM PAL : Sir, it is a very sorry state of affairs that even the senior Finance Minister is misleading the House. They have shown a very steep decline. They

have not risen at all, and the statement placed by them here bears that out. So, I wish them to confirm whether it is so.

... *(Interruptions)* ...

MR. CHAIRMAN : Anything more to add, Mr. Minister?

SHRI MANMOHAN SINGH : I think it is certainly true that the prices of some commodities in January 1993 were lower than they were in March 1992, but I don't think this is something about which one should say that it is inherently wrong. The prices of our agricultural commodities in the year 1991-92 had risen very steeply. If I remember correctly, the previous year the prices of agricultural commodities had gone up as much as 35 per cent with the result that in the previous year inflation was largely a primary commodities phenomenon. This year the primary commodity prices have been a stabilizing influence.

MR. CHAIRMAN : Shrimati Basanti Sarma.

SHRI SOM PAL : Mr. Chairman, Sir . . . . *(Interruptions)* . .

SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Chairman, Sir . . . .

MR. CHAIRMAN : No, please. He has got the answer. Yes, Shrimati Basanti Sarma.

SHRI SOM PAL : Mr. Chairman, Sir, I need your protection again. I am again saying, with particular emphasis, that the prices of agricultural commodities . . .

MR. CHAIRMAN : Now the Minister has given the substance of the answer.

SHRI SOM PAL : The Minister has not given the right reply. It is a totally wrong information, a misleading information. I can show him . . .

MR. CHAIRMAN : I don't think it is a wrong information It is a different way of putting the degree of it. He said it was responsible for that.

SHRI SOM PAL : No, Sir. He says that they have shown a rise. They have not shown a rise. They have shown a steep decline and they have been selling below the minimum support prices, and they have not come out with any reply. But this is no way : he tries to reply out of memory rather than based on facts.

MR. CHAIRMAN : Shrimati Basanti Sarma.

SHRIMATI BASANTI SARMA : I would like to know from the hon. Minister whether the Government has promised to reduce the prices of tea and coffee, and, if so, the reason for the increase in the price of Uttam Tea that is supplied by the Government to the common man. It was Rs. 48 per kg. before the Budget, but now it is Rs. 60 per kg.

डा० अबरार अहमद : सर, सरकार का प्रयास तो हमेशा यही रहता है कि चाय और कॉफी तथा इस जैसी और जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनका भाव कम से कम बढ़े जिससे कंज्यूमर्स पर कम से कम भार पड़े ।

जहां तक माननीय सदस्या ने इसके भाव 48 रुपए से 60 रुपए हो जाने की बात कही है, तो इस समय चाय और कॉफी के भाव 48 रुपए से 60 रूपए होने की मुझे जानकारी नहीं है । मैं अवश्य इसकी जानकारी करूंगा ।

SHRI S. JAIPAL REDDY : Mr. Chairman, Sir, the Finance Minister was good enough to agree that there was no significant rise in the prices of agricultural produce in the current year. Does he realise that the terms of trade for the agricultural sector have always been adverse ? In the current year the prices of inputs such as fertilizers and pesticides have gone up steeply on account of the policy of the Government, the prices of agricultural produce have fallen, and the terms of trade have become all the more adverse. So, what does the Minister intend to do redress this imbalance to help the farmers ?

SHRI MANMOHAN SINGH : Mr. Chairman, Sir, the fluctuations in the terms of trade cannot be helped. But, as I mentioned, in 1991 and 1992 there was a sharp improvement in the terms of trade in favour of agriculture. It is certainly true that as a result of the rise in the

prices of fertilizers there will be some deterioration, but our Government has taken adequate care that the procurement prices are increased more than the rise in the prices of fertilizers.

DR. NAUNIHAL SINGH : There is rise in the cost of input, but the prices which you have given to the farmer for his commodity, for his produce, is not commensurate with the rise in the cost of input.

SHRI MANMOHAN SINGH : Sir, in all these matters one has to go by expert advice. Government has the Agricultural Prices Commission. The Agricultural Prices Commission goes into the cost of production of principal agricultural commodities for every crop season. Government has improved upon the recommendations of the Agricultural Prices Commission in every single case in the last two years.

DR. NAUNIHAL SINGH : Do you consult the farmer? I am a farmer. The farmer is not consulted.

SHRI ASHIS SEN : I am overwhelmed by the very pleasant picture that has been presented by the Minister here. He said that the fertilizer price has increased and yet the benefit has gone to the farmers. May I know to what extent this benefit has been received by the farmers, how far it has reached them?

The second point is, the pleasant picture that he has given is that the prices have gone down in respect of rice, *masoor, urad,* groundnut and oil group. Even the prices of match-boxes have also somewhat been reduced.

I do not know. My only question is whether the Minister or those who have prepared the list, go to the market and do the purchasing themselves, or they are imagining it and preparing this list. Do they go to the market to verify whether what they have stated in the list is correct or not? My question is very simple. Do they go to the market and find out whether what they are giving to Parliament is the actual position in the market?

MR. CHAIRMAN : The answer is simple.

डा० अबरार अहमद : सर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कीमतों में कमी की, वह तो हमने स्वयं हमारे मूल प्रश्न के उत्तर में स्वीकारा है। इसलिए उसमें तो कोई कंट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। जहां तक स्वयं बाजार जाकर खरीदने वाली बात है, तो निश्चित रूप से हम खुद भी बाजार में जाते हैं, मैं तो अपनी कह सकता हूं। मैं खुद भी बाजार जाता हूं और यह देखा है कि इन चीजों की, जिनका माननीय सदस्य ने नाम लिया है, कीमत कम हुई है लेकिन जहां तक आपने किसान की बात कही है फर्टिलाईजर के साथ जोड़कर तो जो सपोर्ट प्राईस में बढ़ोत्तरी की है और इस वर्ष पहले की तुलना में अधिक की है। उसका कारण यही रहा है कि जो फर्टिलाईजर की कीमत बढ़ी है वह किसान को कम्पनसेट कर सके और उसके बदले में वह कुछ दे सके ताकि उसको उसका अधिकार मिले।

SHRI ASHISH SEN : Sir, facts are facts. He is stating fiction. The House is not concerned with fiction. We want to hear the realities and what the Government has in mind. We don't want mere fiction. We want the practical and real picture of the prices of products in the market.

SHRI B. K. HARIPRASAD : I would like to know from the hon. Minister whether, before taking a decision on introducing a dual pricing in respect of kerosene and LPG by partially decanalising their imports for sale outside the public distribution system, any consumer protection organisation was consulted. If so, what was their reaction?

Part (b) of my question is whether the Government has any proposal to withdraw the subsidy of LPG to save Rs. 1,200 crores, as most of the existing LPG consumers fall under the urban middle class and higher income group.

SHRI MANMOHAN SINGH : This is a question which ought to be addressed properly to the Minister for Petroleum.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO : The hon. Finance Minister has stated that non-agricultural product prices have gone up while the prices of agricultural products have come down. I would like to know if it is not a confession that inflation is brought down at the expense of the agrarian sector.

SHRI MANMOHAN SINGH : I have already answered this question. It is certainly true that in the course of the current year the moderation in inflation is largerly a result of the behaviour of agricultural prices. But if you look back, in the previous two years the sharp increase in inflation rate was also because of the sharper increase in the prices of agricultural commodities. (*Interruptions*) The farmers must have gained a great deal in 1990-91 and 1991-92. There is some correction this year.

SHRI MD SALIM : In part (b) of the original question, "comparative item-wise prices as in November, 1992 and January 1993" were asked for. What the Minister has supplied are the price indices. My point is that the original question has not been answered. When we go to the market we see there is a vast difference between the real prices of the items and the wholesale price index as it is supplied by the Government. So, the blank that they have put here should be filled up first. I would like to know whether the Minister will supply the information that has been asked for, about the comparative prices for the months of November, December and January but which has not been supplied here so that the ordinary man as well as the Members here may not be confused with the indices and percentage change-overs.

डा० अबरार अहमद : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है उस सम्बन्ध में जो होलसेल प्राइस का इंडेक्स है, जनरल इंडेक्स नम्बर है इस संदर्भ में उनको मैं बताना चाहता हूं कि नवम्बर, 1992 में 231.7 और जनवरी, 1993 के अंदर जो घट गया है वह 230.3 है। इसी तरह से एसेन्शियल कमोडिटीज है. . . ।

मोहम्मद सलीम : इंडेक्स के बारे में नहीं है सवाल भाव के बारे में है इक्लुडिंग इंडेक्स। मंत्री महोदय इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं भाव के बारे में नहीं।

[شری محمد سلیم :- انڈیکس کے بارے میں نہیں ہے۔ سوال بھاؤ کے بارے میں ہے انکلوڈنگ انڈیکس۔ منتری مہودے انڈیکس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ بھاؤ کے بارے میں نہیں۔]

डा० अबरार अहमद : माननीय सदस्य अगर भाव के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास जनवरी, 93 के भाव हैं, फरवरी के हैं, पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो पढ़ सकता हूं या भिजवा सकता हूं।

MR. CHAIRMAN : Please supply it to him.

DR. AMRAR AHMED : I will supply it to him. (*Interruptions*) I have got the information. If the Chairman allows me, I can read it out.

MR. CHAIRMAN : There is no time to read out all the prices hare. He will give it to you.

Supply of Equipment for Power Projects

*383. SHRI N.E. BALARAM : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hardly 40 per cent of the orders of the Power Plants to be installed under the Eighth Five Year Plan period, are being placed with the BHEL and the rest are being placed with the foreign suppliers; and

(b) if so, the details thereof and also the reasons therefor ?

[ ] Transliteration in Arabic Script.